उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय

नैनीताल

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री विपिन सांघी

माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी

और

माननीय न्यायाधीश श्री रवींद्र मैथानी

रिट याचिका (एम/एस) सं. 476/2023

14 जून, 2023

मध्य:

ब्राइट एंजल्स एजुकेशनल सोसायटी और अन्य।याचिकाकर्तागण

और

श्री राकेश तोमर और अन्य

..प्रतिवादीगण ---

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील:

विद्वान सलाहकार, श्री सिद्धार्थ सिंह और श्री क्षितिज साह।

न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिएः

(माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री विपिन सांघी के अनुसार)

हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सिंह को सुना है।

2. 23.02.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से, वर्तमान संदर्भ बड़ी पीठ को दिया गया था।उक्त आदेश इस प्रकार हैः

"वर्तमान रिट याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत, याचिकाकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, विकासनगर, देहरादून की अदालत द्वारा ओएस सं. 25/13.02.2023 में पारित आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है।

2. विवादित आदेश द्वारा, विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने प्रतिवादियों के विरुद्ध निषेधाज्ञा के लिए याचिकाकर्ताओं (जो मुकदमे में वादी हैं) के आवेदन पर एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।प्रतिवादियों को अपनी आपत्तियां दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसे 13.03.2023 को वापस किया जा सकता है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य है।इस संबंध में, उनका कहना है कि सीपीसी के आदेश 43 नियम 1 (v) के तहत कोई अपील सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि अंतरिम निषेधाज्ञा देने या इनकार करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

वह राम धनी और अन्य बनाम राजा राम और अन्य, 2011 (2) एआरसी 465 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भी भरोसा करते हैं, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने कहा था कि निषेधाज्ञा का अनुदान देने से पहले सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के आदेश के खिलाफ संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत है।

4. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उक्त निर्णय का आधार सी. पी. सी. की धारा 115 की भाषा है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य में लागू है।वे प्रस्तुत करते हैं कि सी. पी. सी. की धारा 115 की भाषा, जैसा कि उत्तराखंड राज्य में लागू होती है, उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होने वाली भाषा के समान है।5.उत्तराखंड राज्य में लागू सीपीसी की धारा 115 (1) इस प्रकार है:

"धारा 115।पुनरीक्षण।(1) एक वरिष्ठ न्यायालय मूल मुकदमे या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य कार्यवाही में तय किए गए मामले में पारित आदेश को संशोधित कर सकता है जहां आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है और जहां अधीनस्थ न्यायालय ने

(ए) एक ऐसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है; या (बी) इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा; या

(ग) अवैध रूप से या भौतिक अनियमितताओं के साथ अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए कार्य किया।(जोर दिया गया) "

6. ऐसा प्रतीत होता है कि सी. पी. सी. की धारा 115 (1) में "निर्णय किए गए मामले में" शब्दों के उपयोग के कारण संशोधन बनाए रखने योग्य नहीं माना गया है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य पर लागू होता है, और जैसा कि उत्तराखंड राज्य पर भी लागू होता है।

7. मेरे लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त शब्द एक अधिशेष हैं, और उनकी उपेक्षा की जा सकती है।मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यदि सीपीसी की धारा 115 (1) को शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए, जबकि उक्त शब्द "निर्णय किए गए मामले में", उनका शाब्दिक अर्थ दिया जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि संशोधन केवल मूल सूट या अन्य के बाद ही बनाए रखा जा सकेगा। कार्यवाही का निर्णय लिया जाता है, और मूल मुकदमे या अन्य कार्यवाही में पारित एक अंतरिम आदेश के खिलाफ कोई भी संशोधन बनाए रखने योग्य नहीं होगा, भले ही, सी. पी. सी. की धारा 115 (1) के खंड (ए), (बी), और (सी) में निर्धारित शर्तें मूल वाद या अन्य कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान पारित आदेश के संबंध में संतुष्ट हों।

8. इसके अलावा, इसका मतलब यह भी होगा कि मूल मुकदमे या अन्य कार्यवाही के अंतिम निर्णय के बाद एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ दो समानांतर उपचार उपलब्ध होंगे, यानी (i) सीपीसी की धारा 105 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 96 के तहत, और; (ii) सीपीसी की धारा 115 के तहत, जैसा कि उत्तराखंड राज्य पर लागू होता है, यदि सीपीसी की धारा 115 (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) की शर्तें पूरी होती हैं।मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विधायी मंशा एक ही आदेश के खिलाफ दो अलग-अलग और समानांतर उपाय प्रदान करने की नहीं

हो सकती है, साथ ही, सीपीसी की धारा 115 के तहत प्रदान किए गए उपाय को पूरी तरह से नकारने की भी हो सकती है, जैसा कि मूल रूप से तैयार किया गया था।

9. राज्य संशोधन, यदि शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए, तो संसद द्वारा तय किए गए सीपीसी की धारा 115 के तहत प्रदान किए गए उपाय को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रभाव रखता है।क्या राज्य विधायिका सीपीसी की धारा 115 में संशोधन कर सकती थी, जो इसे पूरी तरह से नष्ट करने का प्रभाव रखती है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।प्रासंगिक रूप से, सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 13 "सिविल प्रक्रिया" है, जिसमें इस संविधान के प्रारंभ में सिविल प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी मामले, सीमा और मध्यस्थता शामिल हैं।"सिविल प्रक्रिया संहिता एक केंद्रीय अधिनियम है।प्रथमदृष्टया, राज्य संशोधनों का केंद्रीय अधिनियम के प्रावधान को नष्ट करने का प्रभाव नहीं हो सकता है।

10. इसलिए मेरा विचार है कि सी. पी. सी. की धारा 115 की व्याख्या, जो उत्तराखंड राज्य पर लागू होती है, व्यापक प्रभाव वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर उचित विचार करने की आवश्यकता है।इसलिए, मैं इस मुद्दे को विचार के लिए तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेजता हूं।

1. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को निषेधाज्ञा का कोई एकपक्षीय विज्ञापन अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है, और कार्यवाही अब 13.03.2023 को विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के समक्ष तय की गई है, मैं विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को आवेदन की सुनवाई के लिए आगे बढ़ने का निर्देश देता हूं। याचिकाकर्ताओं/वादीगणों को उक्त तिथि अर्थात 13.03.2023 को निषेधाज्ञा देने और उक्त आवेदन पर सुनवाई के लिए कार्यवाही को आगे स्थगित न करने की मांग की।हालाँकि, मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि मैंने याचिकाकर्ताओं के मामले के गुण-दोष की जांच नहीं की है, यद्यपि इस आदेश को किसी न किसी तरह से मामले में मत की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

12. इस मामले को 12.04.2023 पर बड़ी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।

3. श्री सिंह ने प्रस्तुत किया है कि, संदर्भ देते समय, मुख्य न्यायाधीश ने इस आधार पर आगे बढ़ाया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में, "एक मामले में निर्णय लिया गया" शब्द, जैसा कि उत्तराखंड राज्य पर लागू होता है, यदि इसका शाब्दिक अर्थ लगाया जाए तो इसका मतलब एक ऐसा आदेश होगा जो अंततः पूरी कार्यवाही/मुकदमे का निर्णय करता है।

हालाँकि, वह बताते हैं कि अभिव्यक्ति "मामले का निर्णय" किसी मुकदमे या कार्यवाही के अंतिम निर्णय तक सीमित नहीं है, और इस संबंध में, उन्होंने सबसे पहले, संसद द्वारा बनाई गई धारा 115 के स्पष्टीकरण की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जो इस प्रकार हैः

" व्याख्याइस धारा में, अभिव्यक्ति "कोई भी मामला जिसका निर्णय हो चुका है" में किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान किया गया कोई आदेश, या किसी मुद्दे का निर्णय करने वाला कोई भी आदेश शामिल है।

4. उन्होंने मेजर एस.एस. खन्ना बनाम ब्रिगेडियर एफ.जे. डिलन, एआईआर 1964 एससी 497 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसी की धारा 115 पर विचार किया, और इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से विचार किया कि "मामले का निर्णय" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद संख्या 11 और 12 में उक्त निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"11. अभिव्यक्ति 'केस' सर्वग्राही महत्व का एक शब्द हैःइसमें मुकदमों के अलावा सिविल कार्यवाही भी शामिल है, और यह सिविल अदालत में संपूर्ण कार्यवाही तक धारा में निहित किसी भी चीज़ से प्रतिबंधित नहीं है।'मामला' पद की व्याख्या करने के लिए, मात्र एक संपूर्ण कार्यवाही के रूप में और किसी कार्यवाही के एक भाग के रूप में नहीं, अधीक्षण की शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना होगा जो रिट जारी करने की क्षेत्राधिकार और पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं, और इसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में एक पीड़ित वादकारी को राहत देने से इनकार किया जा सकता है जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, और इसके परिणामस्वरूप घोर अन्याय हो सकता है।

12. यह देखा जा सकता है कि बुद्धूलाल बनाम मेवा राम, आईएलआर 43 सभी 564 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बहुमत का दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित है कि भले ही 'मामला' शब्द का व्यापक अर्थ है, लेकिन उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो सकता है। केवल एक मुकदमे में एक आदेश से लागू किया जा सकता है, जहां मुकदमा और उसका एक हिस्सा तय नहीं किया जाता है, इस भ्रम पर आगे बढ़ाया जाता है कि क्योंकि अभिव्यक्ति 'मामला' में एक मुकदमा शामिल है, उच्च न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकार की सीमाओं को परिभाषित करने में जब संशोधित किया जाने वाला आदेश किसी मुकदमे में पारित आदेश हो तो धारा में अभिव्यक्ति 'मुकदमा' को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।अभिव्यक्ति 'मामला' में एक मुकदमा शामिल है, लेकिन उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमा सुनिश्चित करने में, इसे केवल एक मुकदमे के साथ बराबर करने का कोई वारंट नहीं होगा।

5. हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य पर लागू संशोधित धारा 115 में केंद्रीय अधिनियम की धारा 115 में पाया गया स्पष्टीकरण गायब है।हालाँकि, मेजर एस. एस. खन्ना (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय द्वारा "मामले का निर्णय" अभिव्यक्ति पर विचार किया गया है, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वापस की गई व्याख्या के आलोक में, हमारे लिए यह स्पष्ट है कि "मामले का निर्णय" अभिव्यक्ति का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जा सकता है।

6. हम बलदेवदास शिवलाल और एक अन्य बनाम फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स (इंडिया) पी. लिमिटेड और अन्य, 1969 (2) एस. सी. सी. 201 में उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि 'मामला' शब्द का महत्व किसी कार्रवाई में विवादग्रस्त मामले की संपूर्णता तक सीमित नहीं है।उक्त शब्द सर्वग्राही महत्व का एक शब्द है, और इसमें मुकदमों के अलावा अन्य दीवानी कार्यवाही शामिल है, और सी. पी. सी. की धारा 115 में निहित किसी भी चीज़ द्वारा, दीवानी अदालत में कार्यवाही की संपूर्णता तक प्रतिबंधित नहीं है।

किसी मामले का निर्णय तब किया जा सकता है, जब अदालत मुकदमे के प्रयोजनों के लिए विवाद में शामिल पक्षों के कुछ अधिकार या दायित्व का निर्णय करती है; मुकदमे में प्रत्येक आदेश को सीपीसी की धारा 115 के अर्थ के तहत तय किया गया मामला नहीं माना जा सकता है।

1. उपरोक्त के आलोक में, हमारा विचार है कि जिस मुद्दे को बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए भेजा गया है, वह वास्तव में उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि "मामले का निर्णय" शब्दों का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जा सकता है।इन शब्दों को समझना होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेजर एस.एस. खन्ना (ऊपर) और बलदेवदास शिवलाल (ऊपर) मामले में समझाया है।

8.

संदर्भ का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

9. रोस्टर के अनुसार याचिका को 27.06.2023 को खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

(वीपिन सांघी, मुख्य न्यायमूर्ति)

(मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति)

(रवींद्र मैथानी, न्यायमूर्ति)

दिनांक:14 जून, 2023 निशांत